*निजी कॉर्पोरेट निवेश : 2015-16 में हुई वृद्धि एवं 2016-17 के लिए संभावनाएं**

इस लेख में निजी कंपनियों तथा संयुक्त कारोबारी क्षेत्रों, जो अल्पावधि में कारोबारी विचारों में होने वाले परिवर्तनों की माप उपलब्ध कराते हैं, के निवेश के इरादों के रुझानों का विश्लेषण किया गया है। निवेश के इरादों की माप निजी कॉर्पोरेट परियोजनाओं की लागत के आधार पर की गई है जिनका वित्तपोषण चुनिंदा बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) या प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) के माध्यम से किया है। 2015-16 में चुनिंदा बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से 2014-15 की तुलना में निवेश संबंधी विचारों में थोड़ा सुधार होने के संकेत प्राप्त हुए, किंतु ईसीबी/एफसीसीबी के माध्यम से जुटाई गई निधि में कमी आई। 2015-16 में, कुल मिलाकर 706 कंपनियों ने परियोजनाओं में निवेश करने की योजनाएं तैयार की, जिनकी समग्र लागत ₹1,387 बिलियन रही, जबकि 2014-15 में इस तरह की 828 परियोजनाओं में निवेश (संशोधित) की लागत ₹1,456 बिलियन थी।

2015-16 में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित निजी कॉर्पोरेट परियोजनाएं मुख्यत: 'ऊर्जा', 'सड़कें, पुलों एवं जलमार्गों', 'बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों' तथा 'भंडार एवं पाइपलाइनों' जैसे आधारभूत संरचना उद्योगों से संबंधित थीं। इस तरह के निवेश 'टेक्सटाइल', 'यातायात के उपस्कर एवं पुर्जों' तथा 'खनन एवं उत्खनन' उद्योगों में भी किए गए। दूसरी तरफ, ईसीबी/एफसीसीबी से सहायता प्राप्त परियोजनाओं में 'दूरसंचार' उद्योग का प्रभुत्व कायम रहा। बड़ी परियोजनाओं (₹50 बिलियन एवं उससे अधिक) को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सहायता में निरंतर गिरावट आई - इस तरह की परियोजनाओं की कुल लागत में ऐसी सहायता राशि 2009-10 में 57.5 प्रतिशत थी जो 2015-16 में घटकर 5.7 प्रतिशत रह गई।

किसी भी वर्ष में होने वाले संभावित पूंजीगत व्यय (कैप एक्स) का अनुमान उस वर्ष में अथवा किसी पूर्व के वर्ष में वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने वाली समयबद्ध परियोजनाओं से लगाया जा सकता है। बैंकों/वित्तीय संस्थानों, ईसीबी/एफसीसीबी या आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश में 2011-12 से गिरावट देखी जा रही है , हालांकि ऐसे निवेश को कर्ज के निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से सहायता में वृद्धि हो रही है। 2015-16 में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा होने वाला ₹1,512 बिलियन अनुमानित पूंजीगत व्यय 2014-15 के संशोधित अनुमान से 24.7 प्रतिशत कम रहा। इसके अलावा, 2016-17 में इस अपेक्षाकृत निम्न स्तर के समग्र पूंजीगत व्यय को भी बनाए रखने के लिए 2016-17 में नई परियोजनाओं के लिए ₹838 बिलियन की राशि के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने की जरूरत है।

1. प्रस्तावना

किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निवेश को प्रमुख माना जाता है। वहनीय आर्थिक संवृद्धि तब होती है जबकि पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) नई परियोजनाओं, या कारोबारी गतिविधि के विस्तार के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए या उसमें विविधता लाने के लिए किया जाए। पूंजीगत व्यय तब किया जाता है जब कोई कारोबारी संस्था या तो स्थायी आस्तियों की खरीद करे या वर्तमान स्थायी आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाए जिसके अंतर्गत आस्तियों की उपयोगिता में हुई वृद्धि किसी लेखा वर्ष के बाद भी जारी रहे। निजी एवं संयुक्त कारोबारी क्षेत्र की कंपनियों के पूंजीगत निवेश संबंधी इरादों की सूचना से कारोबारी रुझानों में अल्पावधिक परिवर्तनों का आकलन करने में मदद मिलती है।

इस लेख में निजी एवं संयुक्त कारोबारी क्षेत्र की कंपनियों के निवेश संबंधी इरादों को इस तरह के निवेशों के वित्तपोषण संबंधी विवरणों के आधार पर शामिल किया गया है। कंपनियों द्वारा प्रस्तुत चरणबद्ध योजनाओं से पूंजीगत व्यय के संभावित स्तर की जानकारी मिलती है जो 2015-16 के दौरान किए गए होंगे। आगामी वर्ष (2016-17) के लिए प्रक्रियाधीन परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया गया है।

लेख के शेष भाग की रचना पांच अनुच्छेदों में की गई है। अनुच्छेद 2 में, इस लेख से संबंधित कार्यप्रणाली, इसकी

---

* यह लेख कॉर्पोरेट अध्ययन प्रभाग, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक में तैयार किया गया।' कॉर्पोरेट निवेश : 2014-15 में हुई वृद्धि एवं 2015-16 के लिए संभावनाएं' शीर्षक के अंतर्गत पिछला अध्ययन भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के सितंबर 2015 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

** सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक एवं विदेशी बैक जो अपनी ऋण सीमा का काफी हिस्सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की परियोजनाओं के निधीयन में लगाते हैं तथा वित्तीय संस्थाएं जो परियोजनाओं के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं, नामत: आधारभूत संरचना वित्तीयन कंपनी (आईडीएफसी), भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आईएफसीआई), जीवन बीमा निगम (एलआईसी), ऊर्जा वित्त निगम (पीएफसी), भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक।

व्याप्ति एवं सीमाओं को समाहित करते हुए उपागम को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद 3 में उन नई परियोजनाओं का खांका प्रस्तुत किया गया है जिनकी योजना कॉर्पोरेट संस्थाओं ने 2015-16 के दौरान बनाई। इसमें उन सभी परियोजनाओं को समाहित किया गया है जिनके लिए निधि की उगाही बैंकों/वित्तीय संस्थानों, बाह्य वाणिज्यिक निवेश/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों या प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के माध्यम से की गई है। हालांकि, विस्तृत आंकड़ों के अभाव के कारण भिन्न-भिन्न स्तर पर विश्लेषण सिर्फ संस्थागत रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं आकार-श्रेणी, औद्योगिक क्षेत्र, अवस्थिति/राज्य एवं उद्देश्यों के अनुसार ही किया गया है। अनुच्छेद 4 में कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा 2015-16 एवं बाद के वर्षों में परिकल्पित पूंजीगत व्यय के अनुमानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 में कर्ज के निजी स्थानन एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसी परियोजनाओं में कॉर्पोरेट निवेश के अन्य स्रोतों की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। अंततः, अनुच्छेद 6 में, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के आधार पर वर्ष 2016-17 से संबंधित कॉर्पोरेट निवेश की संभावना दर्शाई गई है।

2. दृष्टिकोण - कार्यप्रणाली, व्याप्ति एवं सीमाएं

इस लेख के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली "इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली" में 13 दिसंबर 1970 को प्रकाशित डॉ. सी. रंगराजन के 'कॉर्पोरेट क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का पूर्वानुमान लगाना' शीर्षक वाले लेख तथा उसके बाद इस उद्देश्य से विभिन्न लेखकों के प्रकाशित होने वाले अध्ययनों पर आधारित है। प्रतिक्रिया देने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त चरणबद्ध विवरणों के साथ में वर्ष में कंपनियों के निवेश (अर्थात पूंजीगत व्यय) संबंधी इरादों की सूचना का भी विश्लेषण पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाने (कैप्चर) में किया जाता है, जिसे इस तरह की परियोजनाओं को लागू किए जाने के दौरान व्यय किया जाना है और विगत वर्षों की प्रक्रियाधीन परियोजनाओं में शामिल किए गए पूंजीगत व्यय से इसकी तुलना गई है। ऐसा किए जाने से किसी वर्ष के पूंजीगत व्यय के संभावित स्तर की गणना की जा सकती है।

ईसीबी/एफसीसीबी/आईपीओ जैसे अन्य माध्यमों से वित्तपोषित परियोजनाओं पर भी विचार किया गया। किसी परियोजना का वित्तपोषण एक से अधिक माध्यम से किए जाने पर भी परियोजनाओं को एक ही बार शामिल किए जाने के संबंध में काफी ध्यान दिया गया है। ईसीबी/एफसीसीबी के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं से संबंधित आंकड़े, भारतीय रिज़र्व बैंक को कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र-83 से तथा आईपीओ के माध्यम से कंपनियों द्वारा उगाही गई राशि की जानकारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से प्राप्त की गई है। जिन परियोजनाओं का वित्तपोषण उक्त में से किसी भी माध्यम के अंतर्गत नहीं किया गया या जिनके वित्तपोषण का आकार ₹100 मिलियन से कम था, उनको इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा, सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया जिनका निजी स्वामित्व 51 प्रतिशत या उससे अधिक था तथा जो परियोजनाएं न्यासों (ट्रस्ट) के माध्यम से संचालित थीं। केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षणिक संस्थानों और वित्तीय संस्थानों इत्यादि को इसमें शामिल नहीं किया गया।

इस अध्ययन में, किए गए पूंजीगत व्यय से संबंधित अनुमान व्यापक तौर पर निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की उन परियोजनाओं पर आधारित हैं जिनको बैंकों/वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी। इस तरह के आंकड़े बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए जाते हैं जिसके विविध प्रकार के हिस्से होते हैं, जैसे कि 'परियोजना की कुल लागत', 'चरणबद्ध विवरण'। इनके साथ ही परियोजना के 'उद्देश्य', 'उद्योग' एवं 'स्थान' के विवरण भी प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि, कॉर्पोरेट निवेश का आकलन इस धारणा पर आधारित है कि कंपनियां व्यापक तौर पर अपने प्रस्तावों की योजना में दर्शाए गए व्यय करेंगी। यह भी नोट किया जा सकता है कि इस लेख में प्रस्तुत किए गए कॉर्पोरेट निवेश के अनुमान पहले के (एक्स एन्टे) हैं तथा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) में उपलब्ध स्थायी कॉर्पोरेट निवेश के बाद के (एक्स पोस्ट) अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3. परियोजनाएं - जिनकी योजना 2015-16 के दौरान बनाई गई

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान परियोजनाओं के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से संलग्न 41 बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों ने 352 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान करने की रिपोर्ट भेजी है जिसके अनुसार परियोजनाओं की समग्र लागत ₹954 बिलियन रही। इसके अलावा, 2015-16 के दौरान 314 कंपनियों ने ₹388 बिलियन राशि के ईसीबी/एफसीसीबी करार किए और 40 कंपनियों ने

सारणी 1 : वर्ष 2014-15 और 2015-16 में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं के व्यय करने का ढंग (पैटर्न)

(₹ बिलियन में)

वर्ष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय →	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014-15 में मंजूर की गई परियोजनाएं	परियोजनाओं की संख्या : 326									
	1 (0.1)	148 (17.0)	346 (39.6)	258 (29.5)	95 (10.9)	12 (1.4)	2 (0.2)	10 (1.2)	- -	873 (100.0)
2015-16 में मंजूर की गई परियोजनाएं	परियोजनाओं की संख्या : 352									
	- -	38 (4.0)	78 (8.2)	397 (41.6)	295 (31.0)	82 (8.6)	50 (5.2)	12 (1.2)	2 (0.2)	954 (100.0)

- : शून्य / नगण्य
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत में प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।

2015-16 के दौरान घरेलू इक्विटी जारी किए जाने के माध्यम से ₹45 बिलियन का निवेश जुटाया। इन कंपनियों ने प्रतिक्रिया दर्शाने वाले बैंकों/वित्तीयसंस्थानों से वित्तीय सहायता नहीं ली। इस प्रकार से, 2015-16 में कुल मिलाकर 706 कंपनियों ने निवेश योजनाएं तैयार किया जिनका समग्र मूल्य ₹1,387 बिलियन रहा, जबकि 2014-15 में 830 कंपनियों ने कुल मिलाकर ₹1,459 बिलियन के निवेश संबंधी इरादे व्यक्त किया था (रद्द /संशोधन किए जाने के कारण यह अनुमान संशोधित किया गया जिसके अनुसार निवेश राशि ₹1,456 बिलियन तथा कंपनियों की संख्या 828 दर्शाई गई)।

3.1 बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजनाओं के वित्तपोषण में वृद्धि हुई

2015-16 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की समग्र लागत को ध्यान में रखते हुए निवेश का परिदृश्य थोड़ा बेहतर मालूम पड़ता है। वर्ष 2015-16 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ₹954 बिलियन के समग्र निवेश इरादों के साथ 352 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया जबकि 2014-15 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ₹873 बिलियन मूल्य की 326 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया था। 2015-16 में दी गई नई स्वीकृतियों के चरणबद्ध विवरणों से स्वीकृति के वर्ष में कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग 41.6 प्रतिशत (₹397 बिलियन) खर्च करने की योजना बनाई गई थी, और अगले वर्ष (2016-17) में कुल प्रस्तावित व्यय से और 30.9 प्रतिशत (₹295 बिलियन) राशि खर्च किया जाना था। बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला कि वर्ष 2016-17 के बाद ₹146 बिलियन (15.3 प्रतिशत) की राशि खर्च करने का प्रस्ताव किया गया था। विगत वर्ष के अध्ययन के अनुसार, स्वीकृति की अवधि से दो वर्षों के बाद 13.7 प्रतिशत के तुल्य राशि का संचयी ढंग से व्यय किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। 2015-16 में स्वीकृति प्राप्त करने वाली कुल परियोजनाओं की लगभग 12 प्रतिशत लागत विगत वर्ष अर्थात 2013-14 एवं 2014-15 में पहले ही खर्च की जा चुकी है (सारणी 1)।

3.1.1 परियोजनाओं का औद्योगिक स्वरूप - आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के हिस्से में थोड़ी वृद्धि हुई

परियोजनाओं के औद्योगिक रूप के विश्लेषण से पता चला कि निवेश परिदृश्य के अंतर्गत परियोजनाओं की कुल लागत में 56.7 प्रतिशत हिस्सा के साथ 'ऊर्जा' क्षेत्र का वर्चस्व जारी रहा। 2015-16 में 'सड़क, पुल एवं जलमार्ग', 'बंदरगाह एवं हवाई अड्डा', 'खनन एवं उत्खनन' जैसे क्षेत्रों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि देखी गई, जबकि 'धातु', 'सीमेंट' 'निर्माण-कार्य/कंस्ट्रक्शन' एवं 'होटल तथा रेस्टारेंट' जैसे अन्य प्रमुख उद्योगों का योगदान पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। यह नोट किया जा सकता है कि 2015-16 में कुल परियोजना लागत में 'सड़क, पुल एवं जलमार्ग' क्षेत्र का योगदान बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गया जो 2014-15 में नगण्य था। इसी तरह से, 'भंडारण एवं पाइपलाइन' क्षेत्र की हिस्सेदारी में 4.0 प्रतिशत वृद्धि हुई जो विगत वर्ष 0.3 प्रतिशत थी। 2015-16 में कुल परियोजना लागत में आधारभूत संरचना क्षेत्र (जिसके अंतर्गत 'ऊर्जा', 'सड़क, पुल एवं जलमार्ग', 'बंदरगाह एवं हवाई अड्डा' तथा 'भंडारण एवं पाइपलाइन') की हिस्सेदारी 72.7 प्रतिशत रही, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। वर्ष 2015-16 में भी आधारभूत संरचना की परियेजनाएं बढ़कर 114 हो गईं जो विगत वर्ष 73 थीं (चार्ट 1 एवं संलग्नक-I)।

चार्ट 1 : संस्थागत रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सकल लागत में प्रमुख उद्योगों का हिस्सा

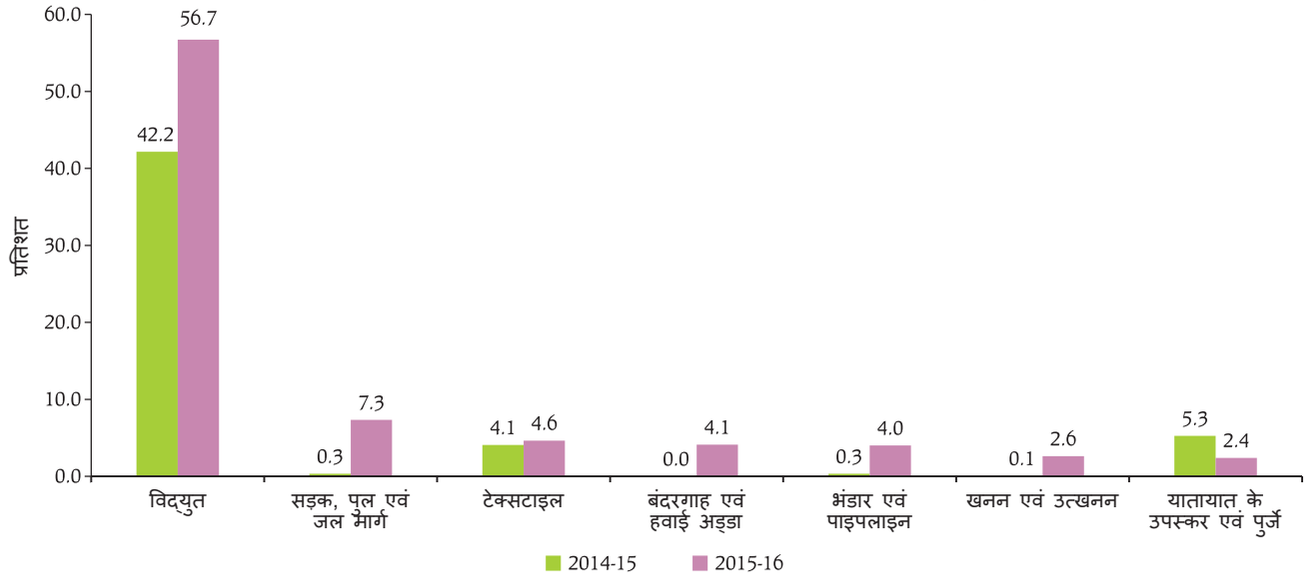

3.1.2 परियोजनाओं का आकारानुसार स्वरूप - 2015-16 में कमजोर हुईं बड़े मूल्य वाली परियोजनाएं

2015-16 में परियोजनाओं की समग्र लागत में पिछले वर्ष की तुलना में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद जो वृद्धि नजर आती है वह सिर्फ कम मूल्य वाली परियोजनाओं से हुई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹10 बिलियन से कम थी। 2015-16 में कुल परियोजना लागत में बड़े मूल्य वाली परियोजनाओं (₹10 बिलियन एवं अधिक) के हिस्से में कमी आई है। इस वर्ष इनकी हिस्सेदारी 44.5 प्रतिशत रह गई जो पिछले वर्ष 59.8 प्रतिशत थी। यह भी देखा गया कि बहुत बड़ी परियोजनाओं (₹50 बिलियन से अधिक) में 2009-10 से कमी आ रही है और 2015-16 में यह अपने निम्नतम स्तर 5.7 प्रतिशत पर पहुंच गई (संलग्नक-II)।

3.13 परियोजनाओं की राज्य-वार रूपरेखा - उद्योग की प्राथमिकता का प्रदर्शन

परियोजनाओं का स्थान वर्ष-दर-वर्ष बदलता रहता है जो कच्चे माल की उपलब्धता, परियोजनाओं की प्रकृति, कुशल मजदूरों की उपलब्धता, पर्याप्त आधारभूत संरचना, बाजार के आकार, वृद्धि की संभावनाएं, उत्पादों के आपूर्तिकर्ता एवं मांग, इत्यादि पर निर्भर करता है। जोपरियोजनाएं बहुत से राज्यों में वितरित हैं उन्हें इस लेख में 'बहु-राज्यी' परियोजनाओं की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। पिछले पांच वर्षों *अर्थात्* 2011-12 से 2015-16 तक में निवेश के आंकड़ों की स्थानिक रूपरेखा से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान परियोजना की समग्र लागत में से 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय महाराष्ट्र, ओडिसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में किया गया है (चार्ट 2 ए)।

पिछले पांच वर्षों *अर्थात्* 2006-07 से 2010-11 की अवधि की रूपरेखा से तुलना की जाए तो पता चलता है कि 'बहुराज्यी' परियोजनाओं का अधिक हिस्सा तब की अवधि में

चार्ट 2 ए : 2011-12 से 2015-16 के दौरान संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण

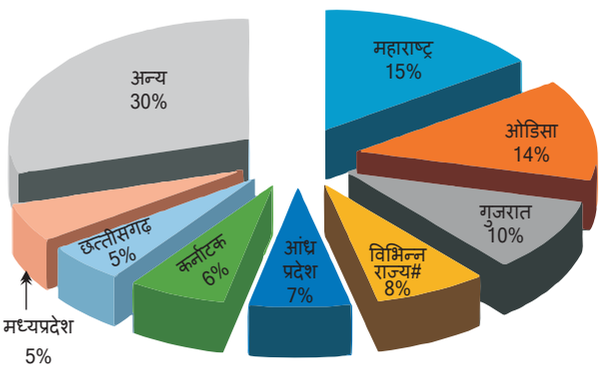

विभिन्न राज्यों में बंटी हुई परियोजनाएं

चार्ट 2 बी : 2006-07 से 2010-11 के दौरान संस्थागत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण

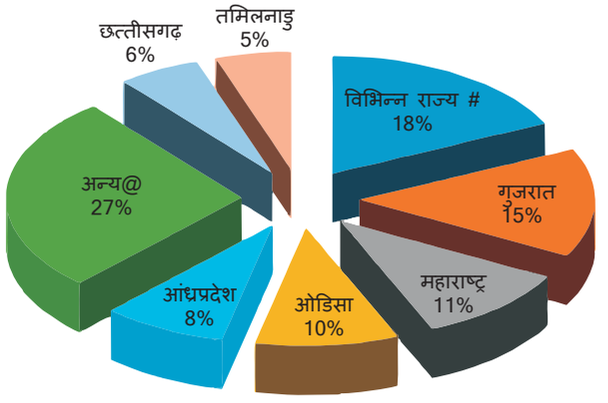

विभिन्न राज्यों में बंटी हुई परियोजनाएं'

था। इसके अलावा, शीर्ष में वही चार राज्य थे, उनके हिस्सेदारी का सिर्फ क्रम परिवर्तित था (चार्ट 2बी)।

2015-16 में संस्थागत रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की लागत के मामले में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश की कुल मिलाकर हिस्सेदारी 64.6 प्रतिशत थी। महाराष्ट्र को छोड़कर, इन सभी राज्यों में 'ऊर्जा' परियोजनाओं का वर्चस्व रहा। महाराष्ट्र में 'बंदरगाह एवं हवाई अड्डा' के विस्तार तथा आधुनिकीकरण को सूची में सर्वोच्च स्थान दिया गया। इसके बाद 'ऊर्जा' का स्थान रहा। बहु-राज्यी' परियोजनाएं भी अधिकांशत: 'ऊर्जा' क्षेत्र की ही थीं। इसके अलावा, 'टेक्सटाइल' क्षेत्र की परियोजनाओं को प्राथमिक रूप से गुजरात एवं तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया। 'सड़कें, पुलों तथा जल मार्गों' के काम को मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में हाथ में लिया गया। 'यातायात के उपस्करों' एवं' कोक तथा पेट्रोलियम परियोजनाओं' की शुरूआत क्रमश: महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में की गई (चार्ट 3)।

3.1.4 परियोजनाओं की उद्देश्य-वार रूपरेखा : नई परियोजनाओं में बेहतर निवेश हुआ

नई परियोजनाओं के उद्देश्य को चार समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि 'नई परियोजनाएं', 'विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाएं', 'विविधता पूर्ण परियोजनाएं' एवं 'अन्य परियोजनाएं'। 'नई परियोजनाओं' के अंतर्गत 2015-16 में काफी सुधार देखा गया, जिनका 2015-16 की कुल परियोजना लागत में 74.6 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा रहा, जबकि 2014-15 में यह हिस्सा 39.7 प्रतिशत था। 'विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजना' समूह के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या में 2015-16 में कमी आई और यह 64 रह गई, जबकि पिछले वर्ष यह संख्य 92 थी। परियाजना लागत में उनकी हिस्सेदारी समान स्तर पर रही (अनुबंध -IV)।

चार्ट 3 : समग्र लागत में संस्थागत रूप से सहायता प्राप्त प्रमुख राज्यों का हिस्सा

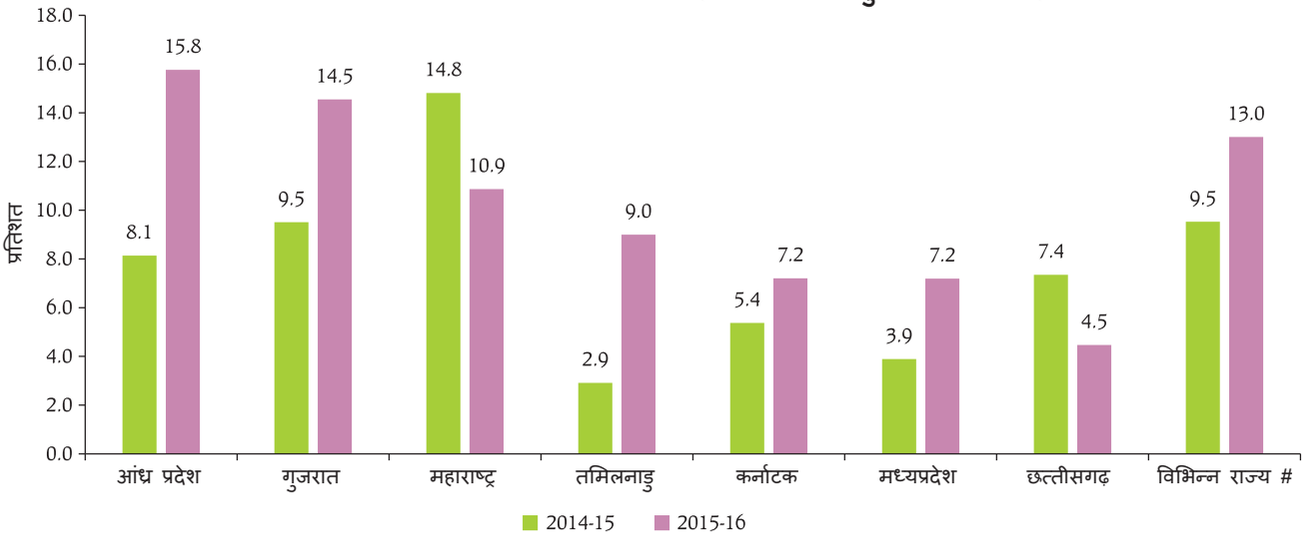

विभिन्न राज्यों में बंटी हुई परियोजनाएं'

3.2 2015-16 में ईसीबी (एफसीसीबी सहित) के माध्यम से परियोजनाओं के निधीयन में कमी आई

बैंकों/वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के अलावा, 2015-16 में पूंजीगत व्यय के लिए निजी क्षेत्र की 314 कंपनियों ने ईसीबी/एफसीसीबी के माध्यम से निधि जुटाई है। इन कंपनियों ने अपनी परियोजनाओं में व्यय हेतु ₹388 बिलियन की राशि एकत्र की। 2014-15 के लिए समरूप आंकड़े थोड़े अधिक थे जो क्रमश: 478 बिलियन एवं 572 बिलियन थे (सारणी 3)। एकत्र की गई कुल राशि में प्रमुख हिस्सा (33.6 प्रतिशत) 'दूरसंचार' सेवाओं का रहा जबकि पिछले वर्ष इसका हिस्सा 8.6 प्रतिशत था।

3.3 आईपीओ/एफपीओ/जारी किए गए अधिकार (राइट्स इश्यूज) के योगदान में वृद्धि हुई

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, पूंजीगत व्यय के लिए आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई निधि के साथ ही आईपीओ के माध्यम से निधि जुटाने वाली कंपनियों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो चुकी है। 40 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों ने अपने पूंजीगत व्ययों के लिए सार्वजनिक/अधिकार जारी करने के माध्यम से ₹45 बिलियन की राशि जुटाई, जबकि 2014-15 में 24 कंपनियों ने ₹11 बिलियन की राशि जुटाई थी। इन परियोजनाओं को बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ईसीबी/एफसीसीबी से सहायता नहीं मिली (सारणी 4)।

4. 2015-16 के दौरान परिकल्पित पूंजीगत व्यय

4.1 बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में परिकल्पित पूंजीगत व्यय में गिरावट आई

परियोजनाओं पर होने वाला पूंजीगत व्यय सामान्यत: कई वर्षों तक जारी रहता है। बैंकों/वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के समय कंपनियों को इस तरह के व्ययों के लिए परिकल्पित योजना दर्शाना होता है। किसी दिए गए वर्ष में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के संभावित निवेश की गणना कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के परिकल्पित समग्र पूंजीगत व्यय संबंधी इरादों को समेकित करते हुए, उस वर्ष तक विभिन्न वर्षों में मंजूर की गई सहायता के आधार पर की जाती है। इस तरह से समेकित किए गए आंकड़े सारणी 2 में दर्शाए गए हैं। इस सारणी का क्षैतिज रूप से अध्ययन करने पर पता चलता है किसी विशिष्ट वर्ष में परियोजनाओं से संबंधित मंजूर की गई सहायता राशि संभावित पूंजीगत व्यय को दर्शाती है। स्तंभ का योग किसी विशिष्ट वर्ष में संभावित पूंजीगत व्यय को दर्शाता है जिसमें उस वर्ष तक (कभी-कभी यह अवधि बाद तक की हो सकती है) विभिन्न वर्षों की मंजूर की गई राशि समाहित है। तथापि, 2015-16 में कंपनियों

सारणी 2 : बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा संस्थागत रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के चरण

मंजूरी का वर्ष↓	मंजूरी के वर्ष में परियोजना की लागत (₹ बिलियन में)	संशोधन/निरसन के कारण परियोजना लागत@ (₹ बिलियन में)	वर्ष में के दौरान परिकल्पित पूंजीगत व्यय (₹ बिलियन में)										
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2007-08 तक	5,678	5051 (11.0)	1,826	1,316	583	375	98	47					
2008-09	4,228	3,111 (26.4)	263	1,013	829	529	346	84	46				
2009-10	5,560	4,095 (26.3)	2	436	1,324	1,161	747	314	77	34			
2010-11	4,603	3,752 (18.5)		3	286	1,071	1,046	788	464	85	1	9	
2011-12	2,120	1,916 (9.6)			57	230	669	554	282	95	29	-	
2012-13	1,963	1,895 (3.5)				1	367	567	490	273	112	65	20
2013-14	1,340	1,273 (5.0)					13	151	348	449	199	71	42
2014-15	876	873 (0.4)						1	148	346	259	95	24
2015-16	954								38	78	397	295	146
कुल जोड़ #			**2,091**	**2,768**	**3,079**	**3,367**	**3,286**	**2,506**	**1,893**	**1,360**	**997**	**535**	**232**
प्रतिशत परिवर्तन					**11.2**	**9.4**	**-2.4**	**-23.7**	**-24.5**	**-28.2**	**-26.7**	*	

: ये प्रत्याशित अनुमान हैं जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। ये वास्तव में प्राप्त हुए/प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।
* : 2016-17 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2016-17 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है वे उपलब्ध नहीं हैं।
@ : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निरसन का प्रतिशत हैं।

सारणी 3: ईसीबी/एफसीसीबी * के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति*

निम्नलिखित वर्षों में ऋण संविदा की गई	कंपनियों की संख्या	कुल संविदा ऋण (₹ बिलियन में)	पूंजीगत व्यय का परिकल्पित प्राप्ति कार्यक्रम (₹ बिलियन में)									
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007-08 तक	1,703	1,427	197	19								
2008-09	272	312	220	121	1							
2009-10	255	324		148	143	22	2					
2010-11	302	316			174	109	27	5				
2011-12	438	379				252	128	19	1			
2012-13	519	660					378	203	63	13		
2013-14	563	803						562	210	31	3	
2014-15	478	572							368	168	32	6
2015-16	314	388								290	73	26
कुल &	**4,844**	**5,182**	**417**	**288**	**318**	**383**	**534**	**788**	**642**	**502**	**108**	**32**
प्रतिशत परिवर्तन					**10.5**	**20.5**	**39.4**	**47.5**	**-18.6**	**-21.8**	**#**	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थानों/आइपीओ से सहायता नहीं प्राप्त हुई थी।
: 2016-17 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणन नहीं की गई क्योंकि 2016-17 में परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले पूंजीगत व्यय के आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं।
& : ये प्रत्याशित अनुमान हैं जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। ये वास्तव में प्राप्त हुए/प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।

द्वारा नई परियोजनाओं में हुए निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। वर्ष के दौरान होने वाले पूंजीगत व्यय में कमी आई। यह देखा गया है कि बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा 2015-16 से पहले मंजूर की गई परियोजनाओं में 2015-16 के दौरान ₹600 बिलियन का पूंजीगत व्यय किया जा चुका होगा। इसके अलावा, 2015-16 के दौरान 2015-16 में वित्तीयमंजूरी प्राप्त करने वाली परियोजनाओं पर ₹397 बिलियन की कुल राशि खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार से 2015-16 के दौरान होने वाला समग्र नियोजित पूंजीगत व्यय ₹997 बिलियन होता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26.7 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। ऐसा होना 2011-12 से देखे जा रहे रुझान के जारी रहने का संकेत है (सारणी 2)।

ईसीबी/एफसीसीबी के माध्यम से निधीयन प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में यह देखा गया है कि 2015-16 से पहले मंजूरी प्रदान की गई परियोजनाओं के आधार पर, 2015-16 के दौरान ₹212 बिलियन का पूंजीगत व्यय होने की संभावना है, तथा वर्ष के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं पर 290 बिलियन की अतिरिक्त राशि का व्यय होने की संभावना है। इस प्रकार से, 2015-16 के दौरान, होने वाला अनुमानित समग्र नियोजित व्यय ₹502 बिलियन रहने वाला है, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 21.8 प्रतिशत की कमी होने का पता चलता है (सारणी 3)।

4.3 आईपीओ/एफपीओ/अधिकारी जारी करने (राइट्स इश्यूज) के माध्यम से निधीयन प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के परिकल्पित पूंजीगत व्यय में सुधार हुआ

2015-16 से पहले आईपीओ/एफपीओ/राइट्स इश्यूज के माध्यम से जुटाई गई निधि के संबंध में 2015-16 में ₹7 बिलियन के पूंजीगत व्यय का उपयोग किए जाने की योजना बनाई गई थी। इसके अतिरिक्ति, वर्ष के दौरान जुटाई गई निधियों में से 2015-16 में ₹6 बिलियन की राशि व्यय किया जाना था। इस माध्यम से जुटाई गई निधि में से 2015-16 में किए जाने वाला नियोजित समग्र पूंजीगत व्यय ₹13 बिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की राशि से लगभग दोगुना है (सारणी 4)।

4.4 परिकल्पित समग्र पूंजीगत व्यय में तेजी से कमी आई

पैराग्राफ 4.1, 4.2 एवं 4.3 में दर्शाए गए समग्र आंकड़ों पर विचार करते हुए यह अनुमानहै कि 2015-16 में कंपनियों द्वारा किया गया कुल पूंजीगत व्यय ₹1,512 बिलियन हो सकता था। कंपनियों द्वारा 2015-16 में इसमें से ₹693 बिलियन की राशि नई परियोजनाओं में व्यय किए जाने की

सारणी 4 : इक्विटी निर्गमों के माध्यम से धन उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति *

निम्नलिखित वर्ष के दौरान जारी इक्विटी	कंपनियों की संख्या	परिकल्पित पूंजीगत व्यय (₹ बिलियन में)	कार्यान्वयन का कार्यक्रम (₹ बिलियन में)									
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007-08 तक	158	205	200	5								
2008-09	21	9	8	1								
2009-10	19	17	2	8	7	1						
2010-11	30	21		1	12	6	2					
2011-12	21	10			2	5	3					
2012-13	25	11					5	5	1			
2013-14	21	5							4	1		
2014-15	24	11							2	6	3	
2015-16	40	45								6	28	11
कुल &	**359**	**334**	**210**	**15**	**21**	**12**	**10**	**5**	**7**	**13**	**31**	**11**
प्रतिशत परिवर्तन					**40.0**	**-42.9**	**-16.7**	**-50.0**	**40.0**	**85.7**	**#**	

* : परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ईसीबी/एफसीसीबी से सहायता नहीं प्राप्त हुई।
# : 2016-17 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2016-17 तक को कार्यान्वित किए जाने की संभावनाओं वाली परियोजनाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
& : अनुमान पहले के हैं, जिनमें सिर्फ परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। ये वास्तविक प्राप्त/प्रयुक्त आंकड़ों से भिन्न हैं।

योजना थी। वर्ष 2015-16 में नियोजित कुल नियोजित पूंजीगत व्यय में से खर्च की गई राशि से पिछले वर्ष की तुलना में 24.7 प्रतिशत की तीव्र गिरावट का पता चलता है। वर्ष 2014-15 में समरूप गिरावट 25.2 प्रतिशत थी (सारणी 5)।

5. निजी स्थानन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषण में और वृद्धि हुई

विगत कई वर्षों से, निजी कॉर्पोरेट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कर्ज के निजी स्थानन एवं प्रत्यक्ष विदेशी

सारणी 5 : बैंकों / वित्तीय संस्थानों/आईपीओ/ईसीबी/एफसीसीबी के माध्यम से धन उपलब्ध कराई गई परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय को चरणबद्ध करना

स्वीकृति का वर्ष ↓	कंपनियों की संख्या	परियोजना लागत (₹ बिलियन में)	वर्ष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय (₹ बिलियन में)									
	बैंक/वित्तीय संस्थान/ ईसीबी/एफसीसीबी / आईपीओ		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007-08 तक	5,306	7,996	1,713	607	375	98	47	-	-	-	-	-
2008-09	1,001	3,432	1,241	951	530	346	84	46	-	-	-	-
2009-10	1,003	4,436	438	1,480	1,311	770	316	77	34	-	-	-
2010-11	1,029	4,089	3	287	1,257	1,161	817	469	85	1	9	-
2011-12	1,095	2,305	-	57	232	926	685	301	96	29	-	-
2012-13	958	2,566	-	-	1	367	950	698	337	125	65	20
2013-14	1,056	2,081	-	-	-	13	151	910	663	231	74	42
2014-15	828	1,456	-	-	-	-	1	148	716	433	130	30
2015-16	706	1,387	-	-	-	-	-	38	78	693	396	183
कुल #			**3,395**	**3,382**	**3,706**	**3,681**	**3,050**	**2,686**	**2,009**	**1,512**	**674**	**275**
प्रतिशत परिवर्तन				**-0.4**	**9.6**	**-0.7**	**-17.1**	**-11.9**	**-25.2**	**-24.7**	*	

: आकलन पहले का है, जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश शामिल हैं। ये वास्तविक प्राप्त/प्रयुक्त आंकड़ों से भिन्न हैं।
* : 2016-17 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2016-17 तक को स्वीकृति की संभावनाओं वाली परियोजनाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी 6 : कर्ज - निजी स्थानन

अवधि	निर्गम राशि (₹ बिलियन में)
2011-12	270
2012-13	591
2013-14	560
2014-15	974
2015-16	1,175

स्रोत : प्राइम (पीआरआईएम) डाटाबेस

निवेश सहित उपर्युक्त से इतर स्रोतों का भी प्रयोग कर रहे हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान, कर्ज के निजी स्थानन के माध्यम से एकत्र की गई निधियों के आंकड़ों से 2013-14 से वृद्धि का रुझान दिखाई देता है। 2015-16 में कर्जों के निजी स्थानन के माध्यम से परियोजनाओं का निधीयन ₹1,175 बिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि निरूपित करता है (सारणी 6)।

2015-16 में इक्विटी में होने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), पुनर्निवेशित आय तथा अन्य पूंजी मिलाकर 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं। एफडीआई के अंतर्वाह में 2012-13 से निरंतर वृद्धि हुई है (सारणी 7)। हालांकि, विशेषरूप से सिर्फ डिबेंचर/बांडों के निजी स्थानन, एफडीआई अथवा अन्य आंतरिक स्रोतोंके माध्यम से निधीयन के माध्यमसे निधि जुटाने वाली कंपनियों के निवेश संबंधी इरादों को उनके अंतिम प्रयोग के संबंध में सूचना नहीं माना गया है, और वर्षों के दौरान रहे व्यय की रूपरेखा अभी उपलब्ध नहीं है।

6. 2016-17 के लिए निवेश की संभावनाएं

इस लेख में सूचित कार्यप्रणाली के अनुसार, 2016-17 में परिकल्पित पूंजीगत व्यय परियोजनाओं पर किए जाने वाले विचाराधीन व्ययों, जिनको उस वर्ष के पहले नहीं खर्च किया गया होगा और वर्ष 2016-17 में संभावित व्यय के प्रस्तावों

सारणी 7 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

अवधि	कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश* (₹ बिलियन में)
2011-12	46.55
2012-13	34.29
2013-14#	36.04
2014-15#	45.14
2015-16#	55.45

* : कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इक्विटी, पुनर्निवेशित आय एवं अन्य पूंजी समाहित हैं।
# आंकड़े अनंतमि है।
स्रोत : डीआईपीपी, भारत सरकार।

का योग होगा। तदनुसार, यदि कंपनियां अपनी निवेश योजनाओं के अनुसार कार्य करती हैं तो 2016-17 के लिए नियोजित पूंजीगत व्यय ₹674 बिलियन होगा (बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से ₹535 बिलियन, ईसीबी/एफसीसीबी से ₹108 बिलियन तथा घरेलू इक्विटी जारी किए जाने के माध्यम से ₹31 बिलियन)। 2015-16 में परिकल्पित पूंजीगत व्यय के स्तर को कायम रखने के लिए 2016-17 में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को नए निवेश इरादों से ₹838 बिलियन का पूंजीगत व्यय किया जाना होगा।

बहरहाल, मांग चक्र के पुनरूज्जीवित होने की अनिश्चितता के निजी कॉर्पोरेट संस्थानों के निवेश संबंधी निर्णयों से प्रभावित होगी, किंतु सरकार द्वारा भारत में कारोबार करने को सुगम बनाने के प्रयासों का सकारात्मक असर पड़ सकता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन में सुधार, जिसमें इस क्षेत्र का लीवरेज भी शामिल है, आने वाले वर्षों में आशान्वित रहने की वजह हो सकती है (भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2016)। इसके अलावा, 2015-16 के दौरान बाधित परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने में होने वाली प्रगति तथा सरकारी परियोजनाओं के पुनरूज्जीवित होने से, जैसा कि सीएमआईई डाटाबेस से स्पष्ट हुआ, निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है।

बैंकों द्वारा वित्तपोषित उच्च मूल्य की परियोजनाओं में पिछले कुछ वर्षों में बारंबार गिरावट देखी गई और आगामी दो तिमाहियों में भी यह रुझान जारी रहने की संभावना है। बैंकों द्वारा तुलन पत्रों को परिशोधित किए जाने के कारण हो सकता है कि निकट भविष्य में वे उनता अधिक ऋण न दे पाएं। हालांकि, आर्थिक माहौल के अनुकूल रहने से कॉर्पोरेट अब भी अन्य स्रोतों (घरेलू एवं विदेशी पूंजी बाजारों सहित) से वाजिब़ दरों पर निधि जुटा पाने की स्थिति में होंगे। एफडीआई के संबंध में सरकार के नए नीतिगत उपायों से वर्तमान में सभी क्षेत्रों में हो रहे एफडीआई के अधिक अंतर्वाह के हाल के रुझान को मजबूती मिलने की संभावना है। सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उच्च मूल्य वाले स्पेक्ट्रमों की नीलामी से 'दूरसंचार' उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना है। यह विचार भी प्रकट किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होने से घरेलू मांग पुन: बढ़ सकती है जिससे वृद्धि तीव्र हो सकती है। इसके अलावा, मानसून के पर्याप्त रहने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने और घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है। ये कारक निकट भविष्य में निवेश की संभावना को परिवर्तित करने में सहायता कर सकते हैं।

संलग्नक 1: संस्थागत रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्योग-वार वितरण : 2006-07 से 2015-16

उद्योग	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर
आधारभूत संरचना	123	36.5	124	39.4	97	45.1	100	48.9	120	53.7	107	47.4	88	49.2	87	39.8	74	48.8	114	72.8
i) बिजली	62	18.3	60	29.4	54	27.9	75	30.7	104	46.2	82	42.4	71	39.4	70	35.1	65	42.2	97	56.7
ii) दूरसंचार	9	6.5	7	1.6	6	10.9	6	16.4	2	5.7	1	0.0	2	5.6	1	-	1	4.9	1	0.3
iii) बंदरगाह एवं एयरपोर्ट	7	3.9	6	0.9	4	2.8	2	0.3	1	0.7	1	1.3	1	1.9	1	0.8	-	-	4	4.1
iv) भंडारण एवं जल प्रबंधन	5	4.6	4	2.1	2	0.0	2	0.9	1	0.0	12	0.5	-	-	5	1.1	2	0.6	4	4.0
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक तथा आइटी पार्क	37	3.1	47	5.4	28	3.2	15	0.6	12	1.1	11	3.2	8	0.9	8	1.5	3	0.9	1	0.4
vi) सड़कें एवं पुल	3	0.1	-	-	3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.2	3	0.3	7	7.3
टेक्सटाइल	255	9.2	116	4.5	45	1.2	77	2.2	77	2.9	94	7.0	31	1.9	58	10.3	50	4.1	49	4.6
खनन एवं उत्खनन	8	0.1	8	0.5	7	0.6	10	2.5	1	0.2	4	0.2	2	0.1	1	0.6	2	0.1	10	2.6
परिवहन के उपस्कर एवं कल-पुर्जे	29	1.9	38	3.5	30	3.0	25	1.3	28	0.8	26	2.6	17	0.9	16	1.2	7	5.3	4	2.4
कंस्ट्रक्शन	33	3.2	38	3.9	30	10.8	20	11.5	18	3.3	22	1.7	20	2.8	27	2.1	29	4.0	27	2.1
पेट्रोलियम उत्पाद	10	14.3	5	7.5	4	0.1	2	1.3	3	2.6	3	1.2	-	-	1	0.5	1	3.4	2	1.9
सीमेंट	26	3.7	24	5.9	28	6.0	29	2.8	14	2.4	9	2.0	11	3.9	12	7.1	7	3.8	5	1.8
खाद्य उत्पाद	38	0.9	41	0.7	50	1.0	41	0.5	39	0.7	41	1.5	36	0.9	43	1.8	34	2.9	26	1.7
रसायन एवं कीटनाशक	35	1.5	25	1.0	27	1.7	28	0.8	27	1.3	17	3.5	19	1.1	15	1.0	7	2.6	11	1.6
धातु एवं धातु के उत्पाद	130	14.5	122	15.6	97	17.7	134	18.1	113	21.1	73	16.3	51	28.9	44	17.0	17	17.4	14	1.5
होटल एवं रेस्तरां	74	4.0	51	3.9	57	2.8	56	2.6	63	3.5	51	4.6	31	3.1	29	2.7	15	1.1	16	1.1
परिवहन सेवाएं	17	0.6	17	1.4	14	1.0	22	1.4	14	0.6	19	2.7	16	1.7	15	0.5	5	0.6	10	1.1
कांच एवं मिट्टी के बर्तन	9	0.3	9	0.4	6	0.3	9	0.2	6	0.4	10	1.3	3	-	11	0.3	19	0.7	8	0.5
चीनी	33	3.2	16	1.3	21	1.2	21	0.8	21	0.8	12	1.1	5	0.5	8	0.8	6	1.3	5	0.4
मनोरंजन	20	0.3	10	0.5	19	1.2	12	1.1	5	0.8	9	1.3	7	0.2	9	2.5	2	0.3	2	0.3
बिजली के उपस्कर	22	0.4	26	0.9	17	1.3	16	0.2	24	2.0	12	0.3	10	1.9	9	2.0	7	0.2	3	0.2
अन्य*	183	5.5	198	9.1	159	5.2	127	3.9	124	2.9	127	5.1	73	4.3	87	9.8	44	3.3	46	3.4
कुल	**1045**	**100**	**868**	**100**	**708**	**100**	**729**	**100**	**697**	**100**	**636**	**100**	**414**	**100.0**	**472**	**100**	**326**	**100**	**352**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ बिलियन में)	**2,754**		**2,297**		**3,111**		**4,095**		**3,752**		**1,916**		**1,895**		**1,273**		**873**		**954**	

*: इनमें औषधीय एवं ड्रग्स, एवं संबद्ध् गतिविधियां, अस्पताल, कागज़ एवं कागज़ के उत्पाद, छपाई एवं प्रकाशन, रबड़, आइटी, साफ्टवेयर, संचार एवं व्यापार आदि जैसे उद्योग शामिल हैं।

-: कुछ नहीं / नगण्य ।

संलग्नक 2 : परियोजनाओं का आकार-वार वितरण तथा 2006-07 से 2015-16 में उनकी परिकल्पित लागत

अवधि		₹1 बिलियन से कम	₹ 1 बिलियन से ₹5 बिलियन तक	₹ 5 बिलियन से ₹10 बिलियन तक	₹ 10 बिलियन से ₹ 50 बिलियन तक	₹ 50 बिलियन एवं उससे अधिक	कुल*
2006-07	परियोजनाओं की सं.	714	245	37	41	8	**1,045**
	प्रतिशत शेयर	9.5	19.4	9.1	31.4	30.6	**100.0 (2754)**
2007-08	परियोजनाओं की सं.	558	228	35	43	4	**868**
	प्रतिशत शेयर	9.3	22.5	10.7	38.3	19.3	**100.0 (2297)**
2008-09	परियोजनाओं की सं.	420	194	35	48	11	**708**
	प्रतिशत शेयर	5.1	14.1	7.5	29.7	43.7	**100.0 (3111)**
2009-10	परियोजनाओं की सं.	439	189	40	39	22	**729**
	प्रतिशत शेयर	3.8	11.0	6.8	20.8	57.5	**100.0 (4095)**
2010-11	परियोजनाओं की सं.	412	172	42	51	20	**697**
	प्रतिशत शेयर	4.4	10.2	8.6	29.3	47.5	**100.0 (3752)**
2011-12	परियोजनाओं की सं.	420	145	36	26	9	**636**
	प्रतिशत शेयर	8.3	17.0	13.7	27.6	33.4	**100.0 (1916)**
2012-13	परियोजनाओं की सं.	245	119	20	23	7	**414**
	प्रतिशत शेयर	4.8	14.6	7.3	26.8	46.4	**100.0 (1895)**
2013-14	परियोजनाओं की सं.	306	115	25	21	5	**472**
	प्रतिशत शेयर	8.3	20.0	13.9	29.1	28.7	**100.0 (1273)**
2014-15	परियोजनाओं की सं.	223	65	18	19	1	**326**
	प्रतिशत शेयर	9.0	16.6	14.6	47.8	12.0	**100.0 (873)**
2015-16	परियोजनाओं की सं.	213	81	35	22	1	**352**
	प्रतिशत शेयर	8.2	21.5	25.8	38.8	5.7	**100.0 (954)**

*: कोष्ठकों के आंकड़े ₹ बिलियन में परियोजनाओं की कुल लागत हैं।
- : कुछ नहीं / नगण्य ।
टिप्पणी : प्रतिशत शेयर, कुल परियोजना लागत का शेयर है।

संलग्नक 3: संस्थागत सहायताप्राप्त परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण : 2006-07 से 2015-16

State	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर
आंध्रप्रदेश	103	8.7	87	7.8	74	7.6	73	7.1	65	11.4	52	5.1	35	5.7	37	4.0	24	8.1	44	15.8
गुजरात	84	26.3	95	26.4	75	18.4	69	3.2	65	9.6	75	9.0	58	5.6	66	14.5	71	9.5	61	14.5
महाराष्ट्र	140	8.7	141	9.7	110	18.1	117	10.0	71	7.4	86	19.1	67	10.7	76	19.7	38	14.8	37	10.9
तामिलनाडु	156	6.9	94	5.1	63	2.3	66	5.5	93	6.1	58	5.7	22	1.8	33	5.4	27	2.9	26	9.0
कर्नाटक	91	7.2	62	4.1	44	2.4	42	1.4	40	7.2	39	12.0	20	1.6	39	6.2	27	5.4	24	7.2
मध्य प्रदेश	23	1.8	18	0.6	20	7.2	23	4.2	21	5.2	16	5.6	13	3.9	30	6.1	14	3.9	22	7.2
छत्तीसगढ़	13	0.9	10	4.7	16	2.3	23	6.0	31	12.1	11	2.4	9	4.1	16	10.7	8	7.4	8	4.5
हरियाणा	42	1.4	28	1.2	24	1.1	29	2.6	35	0.8	45	1.4	18	1.2	15	1.1	11	1.9	16	3.4
पश्चिम बंगाल	37	1.2	41	2.6	43	3.0	33	2.6	29	3.3	19	4.9	13	1.0	12	1.2	9	1.3	14	3.0
ओड़िसा	23	5.4	21	13.1	15	9.0	25	13.9	25	7.4	15	6.3	10	26.8	10	11.7	5	15.9	6	3.0
उत्तर प्रदेश	60	3.6	41	4.2	32	3.1	27	0.4	32	4.6	42	7.8	26	4.4	21	1.1	20	5.4	15	2.4
पंजाब	48	2.1	29	0.7	23	0.7	23	0.4	38	1.1	37	1.7	12	10.9	28	1.5	6	0.3	11	1.7
हिमाचल प्रदेश	30	0.9	23	1.6	18	0.5	19	0.6	13	0.8	7	0.5	5	0.3	3	1.8	3	0.1	8	1.4
राजस्थान	38	3.6	22	1.2	22	0.6	23	2.9	28	0.8	49	4.9	41	5.3	24	1.4	29	11.1	10	0.8
विविध #	46	9.2	61	10.3	55	19.0	45	29.0	48	16.2	34	4.5	15	7.7	21	6.9	10	9.5	13	13.0
अन्य @	111	12.1	95	6.7	74	4.7	92	10.2	63	6.0	51	9.1	50	8.9	41	6.7	24	2.4	37	2.2
कुल	**1045**	**100.0**	**868**	**100.0**	**708**	**100.0**	**729**	**100.0**	**697**	**100.0**	**636**	**100.0**	**414**	**100.0**	**472**	**100.0**	**326**	**100**	**352**	**100.0**
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ बिलियन में)	**2,754**		**2,297**		**3,111**		**4,095**		**3,752**		**1,916**		**1,895**		**1,273**		**873**		**954**	

: इसमें कई राज्यों की परियोजनाएं शामिल हैं।
@: इसमें अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
टिप्पणी : प्रतिशत शेयर, कुल परियोजना लागत का शेयर है।

संलग्नक 4: 2010-11 से 2015-16 के दौरान संस्थागत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रयोजन-वार वितरण

अवधि		नई	विस्तार एवं आधुनिकीकरण	विविधीकरण	अन्य	कुल *
2010-11	परियोजनाओं की सं.	454	224	6	13	**697**
	प्रतिशत शेयर	66.8	30.9	1.8	0.5	**100.0 (3,752)**
2011-12	परियोजनाओं की सं.	449	172	5	10	**636**
	प्रतिशत शेयर	70.6	23.1	0.1	6.3	**100.0 (1,916)**
2012-13	परियोजनाओं की सं.	303	107	-	4	**414**
	प्रतिशत शेयर	84.2	14.7	-	1.1	**100.0 (1,895)**
2013-14	परियोजनाओं की सं.	361	95	2	14	**472**
	प्रतिशत शेयर	65.2	20.1	-	14.7	**100.0 (1,273)**
2014-15	परियोजनाओं की सं.	203	92	2	29	**326**
	प्रतिशत शेयर	39.4	14.7	0.2	45.7	**100.0 (873)**
2015-16	परियोजनाओं की सं.	266	64	3	19	**352**
	प्रतिशत शेयर	74.6	13.7	0.1	11.6	**100.0 (954)**

*: कोष्ठकों के आंकड़े ₹ बिलियन में परियोजनाओं की कुल लागत हैं।
-: कुछ नहीं / नगण्य ।